an>

Title: Need to formulate a comprehensive Mining policy in the country.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, देश के कई प्रदेशों में पिछले वर्षों में खनन के अंधाधुंध प्रयोग के कारण कई राज्यों ने अपने प्रदेशों में खनन पर प्रतिबंध लगाया है। खनन के प्रतिबंधों के कारण जहां पर्यावरण में फर्क पड़ा है, वहीं इस कारण एक समस्या भी पैदा हुई कि देश की विभिन्न नदियों में रेत का स्तर काफी बढ़ गया है, जिस कारण बाढ़ आना आम बात हो गई है। दूसरी तरफ नियमानुसार खनन न होने से रेत और बजरी के भाव भी आसमान को छूने लगे हैं। एक गरीब व्यक्ति के लिए घर बनाना एक सपना बन गया है। राज्य सरकारों व भारत सरकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत चलने वाली सभी योजनाओं का खर्च भी ईंट, रेत और बजरी के भाव बढ़ने के कारण डबल हो गया है।

महोदया, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए देश में एक पारदर्शी खनन नीति का बनाना अतिआवश्यक है, जो इनक्लूसिव होनी चाहिए न कि एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप देश के आम नागरिक का अपना घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा।